

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर

समक्ष - एम०के०सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 1437-एक/2005 - विरुद्ध - आदेश
दिनांक 7-6-2005 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चम्बल
संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 39/1998-98 अपील

जगन्नाथ पुत्र किशुनलाल कुशवाह
ग्राम लीलहर तहसील कैलारस जिला मुरैना --- अपीलॉट
विरुद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन
2- प्रबंधक मुरैना सहकारी शकर
कारखाना मर्या०कोलारस जिला मुरैना ---रिस्पाडेन्टस

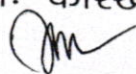
(अपीलांट के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(रिस्पा० के अभिभाषक श्री बी०एन०त्यागी)

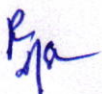
आ दे श

(आज दिनांक ९ - 10 - 2016 को पारित)

यह अपील आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा के
प्रकरण क्रमांक 39/1998-98 अपील में पारित आदेश दिनांक
7-6-2005 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959
की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि रिस्पा०क०-2 ने कलेक्टर
मुरैना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि विमुक्त
जाति सामूहिक कृषि सहकारी संस्था ग्राम धोंधा का विलय
कारखाने में हो जाने से ग्राम धोंधा तहसील जौरा स्थित 82
हैक्टर भूमि दूर हो गई है जिससे उन्नत किस्म का गन्ना उत्पन्न
करने में व्यवधान है अतः कारखाने की सहूलियत के लिये मौजा



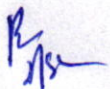


कैलारस स्थित शासकीय चरनोई भूमि रकबा 27-673 का विनियम कर दिया जावे। कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 3/1997-98 अ 19 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 16-12-1997 से भूमि का विनियम करना स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध एक अपील अपीलांट ने एवं द्वितीय अपील मुरारीलाल आदि ने आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 39/97-98 अपील पर एवं 11/2002-03 अपील पर पंजीबद्ध हुई। आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने पक्षकारों को सुनकर संयुक्त आदेश दिनांक 7-6-2005 पारित किया तथा दोनों अपील अस्वीकार कर दीं एवं कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 16-12-1997 को पुष्टिकृत किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलांट के अभिभाषक तथा रिस्पा0 के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

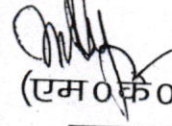
4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि कलेक्टर मुरैना द्वारा वाद विचारित भूमि का विनियम प्रकरण क्रमांक 3/1997-98 अ 19 पारित आदेश दिनांक 16-12-1997 से किया है और यह आदेश उन्होंने राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 20 के अंतर्गत पारित किया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 के अवलोकन से स्थिति यह है राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 20 के अंतर्गत पारित आदेशों की अपील कंडिका 30 के अंतर्गत





कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील आयुक्त को उसके वाद निगरानी राज्य शासन को होगी, जिसके कारण राजस्व मण्डल में प्रस्तुत यह द्वितीय अपील अग्राह्य है क्योंकि इन नियमों के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध एक ही अपील का प्रावधान है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अप्रचलन-योग्य पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा के प्रकरण क्रमांक 39/1998-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-6-2005 यथावत् रहता है।



(एम0के0सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर

R
1/2